

स्टेशन हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) इस काम को पूरा करने के लिये सरकार को कितना समय लगेगा तथा वर्ष 1968-69 में इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :
(क) 343 स्टेशन ।

(ख) अभी यह बताना संभव नहीं है कि मध्य प्रदेश के सभी स्टेशनों पर बिजली कब तक लग जायेगी क्योंकि स्टेशनों का विद्युतीकरण अनेक तत्वों पर निर्भर है, जैसे, आसपास में निम्न वोल्टता की बिजली सप्लाई की उपलब्धता, सर्विस कनेक्शन प्रभार और शुल्क दर का उचित होना, धन की उपलब्धता (चूँकि यह एक निम्न प्राथमिकता की सुख-सुविधा है), रात में रुकने वाली गाड़ियों की संख्या आदि। 1968-69 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेशनों पर बिजली लगाने में लगभग 2,08,000 रुपये खर्च होने की संभावना है।

कोटा सर्किल (पश्चिम रेलवे) में टिकट निरीक्षक कर्मचारी

7979. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के कोटा सर्किल में टिकट निरीक्षक कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पद अभी खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 250-380 रुपये के अधिकृत वेतनमान में एक पद।

(ख) इस पद को भरने के लिए चुनाव किया जा रहा है।

रेलवे के संगचल कर्मचारी

7980. श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री नीतिराज सिंह चौधरी।

श्री श्रोकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में गाड़ों, ड्राइवरों, फायरमैनो तथा ब्रेकमैनो को संगचल कर्मचारी माना जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि संगचल टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी माना जाता है हालांकि वे सभी आयोजनों तथा उद्देश्यों के लिये संगचल कर्मचारियों में आते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्हें वे सुविधायें नहीं दी जाती हैं जो संगचल कर्मचारियों को मिलती हैं; और

(घ) क्या भविष्य में संगचल टिकट निरीक्षकों को संगचल कर्मचारी मानने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) से (घ). केवल उन्हीं कोटियों के रेल कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी माना जाता है जो प्रत्यक्षतः गाड़ियों के संचलन के काम पर लगे हैं और जिन पर इसका उत्तरदायित्व है। इन कर्मचारियों को यात्रा भत्ते और गाड़ियों के संरक्षित, समय पर और त्वरित संचलन, जिस पर कि परिचालन कुशलता निर्भर करती है, के लिए प्रोत्साहन भुगतान के रूप में रनिंग भत्ता दिया जाता है। अन्य अनेक कोटियों के रेल कर्मचारियों की तरह चल टिकट निरीक्षकों को चलती गाड़ियों में काम करना होता है लेकिन वे किसी

भी तरह गाड़ियों के परिचालन अथवा संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारी मानना और रनिंग भत्ता देना सम्भव नहीं है। जब वे गाड़ियों से यात्रा करते हैं, तो उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाता है।

रनिंग कर्मचारी रनिंग कमरों की सुविधा पाने के भी पात्र हैं। जिसके लिए चल टिकट परीक्षक, नियमानुसार पात्र नहीं है। फिर भी, यदि स्थान उपलब्ध हो, तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाती है। जहां कहीं वर्तमान रनिंग कमरों में जगह पर्याप्त नहीं है, वहां उन्हें विश्राम कमरों में जगह देने का प्रयास किया जाता है।

Consultancy Expenditure in Fourth Five Year Plan

7981. SHRI B. K. DAS CHOWDHURY : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has estimated that about Rs. 200 crores would be required for consultancy work during the Fourth Plan; and

(b) if so, whether, Government propose to take steps to reduce this amount to save foreign exchange?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) In the course of a study on the requirements of consultancy services, a rough estimate of the scope of consultancy work arising during the erstwhile Fourth Plan (1966-71) was attempted in 1966. Taking into account the projects for which consultancy services have already been commissioned and adopting certain rough norms, it was estimated that for the Fourth Plan as tentatively formulated at the time, the value of consultancy service that was likely to be required would be about Rs. 200 crores. This does not represent the foreign exchange outflow on account of consultancy service since a considerable part of the consultancy work would also be carried out in the country.

No estimate has yet been prepared of the value of the consultancy services likely to be required for the Fourth Five Year Plan (1969-74) as now finalised by the Planning Commission.

(b) With a view to ensuring maximum possible utilisation of Indian consultancy Services, it has been laid down that wherever Indian consultancy is available it should be utilised exclusively, and if foreign consultancy is also required, Indian consultants should also be associated and, as a rule, be the primary agency employed for consultancy.

Steps have been taken to enlist technical consultancy firms operating in the country for definite fields of engineering and it is expected that in such cases where their services can be utilised, foreign technical consultancy would not be invited or permitted.

Classification of Industries

7982. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : SHRI SITARAM KESRI :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the executive committee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has urged the Government to rationalise its approaches towards classification of industries for the purpose of industrial licensing, import licensing, foreign collaboration and income tax concessions; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Government have not received any such suggestions recently from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(b) Does not arise.

Grinding Machine Tool Plant at Ajmer

7983. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : SHRI GADILINGANA GOWD :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) when the Grinding Machine Tool Plant